

**Title:** Demand to allocate funds to meet the drought situation in Rajasthan.

**श्री शीश राम ओला :** राजस्थान में लगातार तीसरे वर्ष भीषण अकाल पड़ा है। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: If you permit me, I can complete all the notices. There are almost 47 notices. Please do not disturb the Chair.

**श्री शीश राम ओला :** राजस्थान में लगातार तीसरे वर्ष भीषण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके संबंध में मैं आपकी अनुमति से चर्चा करना चाहूंगा। राजस्थान में 41,500 गांव हैं। इस वर्ष 30,583 गांव अकाल की भयंकर चपेट में हैं। 32 जिले हैं जिनमें से 31 जिले भयंकर अकाल से ग्रस्त हैं। पीने के पानी की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। पशुओं के लिए चारे की गंभीर स्थिति है। पिछले वर्ष जुलाई, अगस्त और सितम्बर में पंजाब से गेहूँ का तोड़ा आता रहा जिससे लोगों ने अपने मवेशियों को बचाया जबकि उस वक्त बहुत अच्छी घास होती है। किन्तु उन महीनों में बरसात न होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई। उदयपुर झीलों की नगरी कहलाई जाती है। वहां की सारी झीलें सूखी पड़ी हैं और तीन-तीन, चार-चार दिनों में पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे जिलों जैसे झुंझुनू, सीकर, चुरू, नागौर, बीकानेर आदि, जहां पहले से ही पानी की कमी थी, के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पानी काफी गहरा चला गया है। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Dr. Girija Vyas, you have also given the notice on the same subject. You can also associate with Shri Sis Ram Ola on the same subject.

**श्री शीश राम ओला :** मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि राहत कार्य शुरू करने के लिए राजस्थान के पास पैसा नहीं है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाइए।

**श्री शीश राम ओला :** मैं अपनी बात कहूंगा। मैं कैसे बैठ जाऊं।

**अध्यक्ष महोदय :** अब आपको समाप्त करना है।

**श्री शीश राम ओला :** मैं अपनी बात पूरी करके बैठूंगा। मैंने नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** और माननीय सदस्यों ने भी बोलना है।

**श्री शीश राम ओला :** इसका क्या मतलब है। मैं अपनी बात कहूंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** जीरो आवर में आपको दो मिनट का समय मिलेगा।

**डॉ. गिरिजा व्यास (उदयपुर) :** महोदय, बहुत गहरी समस्या है, इनको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप जीरो आवर में कितना टाइम लेंगे।

**श्री शीश राम ओला :** मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है और बैठ जाऊं। मैं निवेदन करूंगा कि पशुओं के लिए चारा नहीं है। खेतीहर मजदूरों के लिए रोजी नहीं है। किसान बर्बाद हो गया। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसकी आर्थिक स्थिति पशुधन पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में सारा पशुधन बर्बाद हो गया है। मैं निवेदन करूंगा कि खाद्य के भंडार से एफ.सी.आई. के गोदाम भरे पड़े हैं। राजस्थान को खाद्य पदार्थ मुफ्त देना चाहिए ताकि मजदूरों को मजदूरी मिले और राहत कार्य शुरू हो सके। राजस्थान सरकार के पास कैलेमिटी रिलीफ फंड नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाइए।

**श्री शीश राम ओला :** यदि वक्त रहते भारत सरकार आर्थिक सहायता नहीं देगी तो यह स्थिति नहीं संभाली गई तो मुश्किल हो जाएगी। राजस्थान सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है और वहां के लोग मजदूरी के लिए दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। राजस्थान की गंभीर स्थिति को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए। तत्काल राहत कार्य शुरू करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।

**प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) :** मान्यवर, हम लोग राजस्थान से हैं, हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आपने नोटिस दिया था ?

**प्रो. रासा सिंह रावत :** नोटिस तो कल दिया था। राजस्थान में घोर अकाल की स्थिति बनी हुई है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** जीरो आवर का प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अनुसार आपको पहले नोटिस देना चाहिए था।

**प्रो. रासा सिंह रावत :** वहां कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वहां निकम्मी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: This will not go on record आप बैठ जाइये। यह प्रोसीजर नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट इश्यू है तो आपको नोटिस देना चाहिए था।

**डा. गिरिजा व्यास :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान केन्द्र सरकार की उदासीनता ही नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार की निर्ममता की तरफ भी दिलाना चाहती हूँ। अभी जैसा ओला जी ने कहा कि सूखे का यह तीसरा वर्ष है, लेकिन राज्य के 18 जिलों में यह चौथा वर्ष है। अभी गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार 32 में से 31 जिले अभावग्रस्त घोषित हो चुके हैं और करीब चार करोड़ जनसंख्या और करीब उतने ही चार करोड़ पशु इससे प्रभावित हुए हैं। केन्द्र सरकार से अभी हमने 2367 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। पिछले वर्ष केन्द्र सरकार ने पानी के परिवहन के

लिए और टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो साधन उपलब्ध कराये थे, उसके लिए तो हम धन्यवाद देते ही हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत राज्य के लिए इस वर्ष इंगित राशि 180 करोड़ रुपये अभी तक रिलीज नहीं हुई है, जिससे कि हमें थोड़ी राहत मिल सकती। दिसम्बर में तीन लाख लोगों को रोजगार दिये जाने की योजना राज्य सरकार की है और उसके लिए 1560 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगी कि वह पैसा जल्दी रिलीज करें। इसी तरह से 3620 करोड़ रुपये की आवश्यकता हमें पशु संरक्षण के लिए होगी। उसके लिए भी आपसे निवेदन करने की जरूरत महसूस हुई है। मैं सिर्फ एक बात और आपने निवेदन करना चाहती हूँ कि आप एक टीम सांसदों की उन राज्यों में अवश्य भेजें, जिन राज्यों में इस प्रकार से सूखे की विम स्थिति है और वे राज्य एन.डी.ए. सरकार से डायरेक्ट सम्बन्धित नहीं हैं। वहां पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जैसा कल सोमनाथ चटर्जी जी ने भी कहा था और जैसा दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। कृपया आप इस ओर तुरन्त प्रभाव से सरकार को निर्देश दें।

**अध्यक्ष महोदय :** आपने दो इश्यू दिये हैं, आप किसके बारे में इश्यू रेज कर रहे हैं ?